Result Mitra Daily Magazine

ईरान-US संबंध

❖ हालिया संदर्भ :

- ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने परमाणु सहयोग पर USA से वार्ता पुनः शुरू करने की संभावना पर कहा कि 'दुश्मन' के साथ बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है।

❖ JCPOA :

- संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) को ईरान परमाणु समझौते 2015 के नाम से भी जाना जाता है।
- इस समझौते का उददेश्य ईरान पर प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के बदले में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर रोक लगाकर इसे नागरिक प्रकृति (बिजली, ऊर्जा या अन्य नागरिक उद्देश्य) का बनाना था।

Result Mitra

- इस समझौते को P5+1 समझौते भी कहा जाता है, जिसमें चीन, फ्रांस, USA, ब्रिटेन एवं रूस (UN के 5 स्थायी सदस्य) तथा जर्मनी एवं यूरोपीय संघ शामिल थे।
- इस संधि के तहत ईरान इस बात पर सहमत हुआ था कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु संयंत्रों की निरीक्षण की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा है।
- वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने USA को इस संधि से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद यह समझौता खत्म हो गया।
- यह अंतिम घटना थी, जब ईरान एवं USA के बीच कोई समझौता हुआ था।
- समझौता रद्द होने के बाद ईरान संबंध ज्यादा खरब हो गए और वर्तमान में दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक संबंध नहीं है, लेकिन दशकों पूर्व ऐसा नहीं था।

❖ 1953 का तख्तापलट :

- ईरान में 1953 में हुए तख्तापलट ईरान-US संबंध के दौर में एक महत्वपूर्ण घटना थी।
- 1953 से वर्षों पूर्व से ईरान के तेल संसाधनों पर ब्रिटेन का नियंत्रण था लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ईरान के नेता चुने गए मोहम्मद मोसादेग के शासनकाल में इसमें परिवर्तन आया।
- प्रधानमंत्री मोसादेग ने ब्रिटिश तेल कंपनी के दस्तावेजों के ऑडिट करवाने की मांग की एवं ईरानी तेल संसाधनों पर ब्रिटिश कंपनी के अधिकार को सीमित कर दिया।
- ईरानी संसद (मजलिस) ने ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा विदेशी तेल निगमों को देश से बाहर निकाले जाने का समर्थन किया।
- जवाब में ब्रिटेन ने ईरान से सभी राजनयिक संबंध तोड लिए एवं विश्व की सबसे बडी ब्रिटिश तेल कंपनी अबादान तेल रिफाइनरी (ईरान में स्थित) पर कब्जा करने के लिये सैन्य बलों का प्रयोग किया।

Result Mitra

- ब्रिटेन एवं USA ने खुफिया एजेंसियों की सहायता से मोसादेग को सत्ता से बेदखल कर दिया और मोसादेग को गिरफ्तार कर लिया गया।
- इस तख्तापलट को USA ने 'ऑपरेशन अजाक्स' एवं ब्रिटेन ने 'ऑपरेशन बूट' नाम दिया।
- शाह या मोहम्मद रजा पहलवी ने USA समर्थन से सत्ता हासिल की और विद्राहियों को दबाने के लिये SAVAK नामक खुफिया एजेंसी की स्थापना की।

Note :- यह USA का पहला गुप्त मिशन था, जिसके द्वारा शांतिकाल में किसी विदेशी सरकार का पदच्युत कर दिया गया हो।

❖ 1979 की क्रांति :

- रजा पहलवी ने सत्ता प्राप्त करने ही ब्रिटेन के साथ सभी संबंधों को बहाल किया एवं USA पर बहुत ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया।
- रजा पहलवी का बढता पश्चिमी देशों से प्रेम, पश्चिमी संस्कृति एवं धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्थन और प्रगतिशील विचारों ने ईरान के जनता ओर मौलवियों को जवाबी करवाई को मौका दे दिया।
- कट्टर इस्लाम समर्थक ईरानी छात्रों एवं मौलवियों ने शाह रजा पहलवी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें धार्मिक विद्वान अयातुल्ला खुमैनी प्रमुख नेता के रूप में उभरे।
- हिंसा और विरोध के फलस्वरूप पहलवी ने देश छोड दिया एवं खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई।

❖ क्रांति के बाद ईरान-US संबंध :

- क्रांति के तुरंत बाद ईरान-बंधक संकट ने दोनों देशों के बीच संबंध को और बिगाड दिया।
- 444 दिनों तक 52 अमेरिकी राजनयिकों एवं नागरिकों को तेहरान में USA दूतावास में क्रांति समर्थकों द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था।

Result Mitra

- दरअसल क्रांति के बाद रजा पहलवी भागकर ईरान चले गए थे और क्रांति समर्थक अमेरिका पर दबाव बनाकर पहलवी को वापस ईरान लाना चाहते थे।
- इस संकट के बाद USA ने ईरान से सभी प्रकार के औपचारिक संबंध खत्म कर लिये।
- USA ने 1980-88 के दौरान ईरान-इराक युद्ध में इराक का समर्थक किया, जिससे आपसी रिश्ते और खराब हो गए।
- तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2002 में ईरान को इराक और उत्तर कोरिया के साथ 'बुराई की धुरी' (Axis of evil) हिस्सा बताया।

❖ US द्वारा ईरान पर प्रतिबंध :

- वर्ष 1979 के बाद से US ने ईरान पर अलग-अलग समय पर कई सारे प्रतिबंध लगाए है, जिनमें प्रमुख है :
- 1979 में कार्यकारी आदेश-12170 द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के अलावा ईरानी लोगों के 12 बिलियन डॉलर मूल्य के संपतित को फ्रीज कर दिया।
- ईरान-इराक युद्ध के दौरान हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि 1984 में US द्वारा ईरान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया गया।
- 2010 के दशक में व्यापक ईरान प्रतिबंध एवं CISADA (जवाबदेही और विनिवेश एक्ट) द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए।
- ईरान सरकार द्वारा US डॉलर खरीदने या रखने पर रोक हैं साथ ही ईरानी मुद्रा रियाल के लेन-देन पर भी रोक है।
- ईरान सरकार को ऋण देने, ईरानी कालीन आयात करने तथा ईरान के साथ सोने या अन्य कीमती धातुओं में व्यापार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

Note :- USA ने उन सभी कंपनियों या देशों, जो ईरान से उक्त प्रतिबंध के बाद भी व्यापारिक संबंध रखते हैं, को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है।

Result Mitra

Result Mitra